considerable extent. And I am given to understand that the Government is thinking of closing down the EIA.

I, therefore, request the Minister of Commerce to withdraw the notification and the executive order cited above and to resist any move to give further relaxation to quality inspection, and to take adequate steps to transform the statutory status of the organisation to a Central Government Department for a better and efficient functioning.

With these words Sir, I conclude. Thank you.

Ill-effect on the economic structure due to a possible Gulf War

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज सारी दुनिया एक विचार से बहुत ज्यादा भयभीत है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया, तो वर्तमान ही नहीं, मानव जाति और इनसानियत का मुस्तकबिल भी खतरे में है।

आज जिस तरह से अमरीका और उसके एलाइज की फौजों ने सऊदी अरब में अड्डा बना लिया है, उससे एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने का डर है। प्रोपोशन से ज्यादा पांच लाख अमरीकंस और उनके एलाई सोल्जर्स इस वक्त खाड़ी में पड़े हुए हैं। इसी के साथ-साथ 75 लड़ाकू यानों के जहाज होरमूज के समुद्र में इधर-उधर घूम रहे हैं और लगभग 7,400 लड़ाई के हवाई जहाज वहां पहुंचा दिए गए हैं।

अभी जेनेवा में बातचीत हो रही है आशा की जाती है, शायद कुछ रिजल्ट्स निकले, लेकिन यूनाइटेड स्टेटस के होम सेक्रेटरी, श्री जेम्स बेकर, ने जिस तरह से लंदन में इशारा किया है कि इस बातचीत से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, इससे हमारे ऊपर यह खतरे और बढ़ गए हैं।

भारत के लोगों को, जो हमेशा-हमेशा विश्व शांति में विश्वास रखते हैं, ज्यादा चिंता पूरे देश की, पूरे विश्व की और विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र की है, मान्यवर, आप जानते हैं कि यदि युद्ध हो जाता है तो वह युद्ध इराक, कुवैत और सऊदी अरब के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे एशिया के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और जो आज दुनिया की इकोनोमी जिस चीज से चलती है और दुनिया की प्रगति और विकास जिस चीज पर पूरी तरह से निर्भर है तेल के सारे कुएं इराक और इरान के विशेष रूप पर जो अमरीका ने उनके ऊपर अपनी मिसाइल फिट की है, वह सब के सब तबाह हो जाएंगे। यदि तेल तबाह हो जाए तब भी एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके साथ-साथ उन कुओं के जलने से, उनको आग लगने से जो धुआं उठेगा और जो जहरीली गैसें उठेंगी उससे हमारे यहां का जलवायु, हमारे यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारी कृषि और हमारी सब कुछ जो आर्थिक व्यवस्था है वह सारी की सारी चरमरा जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इस सिलसिले में कोशिश की है और उन्होंने ईरान से बात की है कि वह पैट्रोल ज्यादा से ज्यादा हम को दे सके। लेकिन ईरान के कुएं भी खतरे में हैं। ऐसी सूरत में जबकि हम अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे तेल के निर्यात का करीब 6400 करोड़ रुपये का बजट हर साल भुगतान होता है लेकिन वह अगर यही परिस्थितियां बनी रही तो 100 डालर प्रति बैरल तेल का हो जाएगा। और हमारे लिए नेक्सट टू इम्पोसिबल जिसे कहते हैं कि इस सूरत में भुगतान संभव नहीं हो पायेगा ऐसी सूरत में जिस तरह कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं हमारा जो आयात करने का जो तेल का बिल होगा वह लगभग 12,400 करोड़ हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भारत को अगुवाई करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध को

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

जिसको मैं समझता हू कि कही यह तृतीय महायुद्ध की सूरत मे परिवर्तित न हो जाए, उसको किसी सूरत मे टाला जा सके। इसी के साथ-साथ जो और हमारी जिम्मेदारियां है उसको हम किसी तरह से निभा सकें, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, मान्यवर, वह इस वक्त डबल डिजिट मे है। 11.6 परसेंट है और लगता है कि जो हालात चल रहे है उसमे यदि ऐसी कैफियत रही तो यह डबल हो जाएगा। यदि जंग हो जाती है तो यह हमारा जो इन्फ्लेशनरी रेट है वह 30-35 तक पहुच सकता है ऐसी परिस्थितियो मे हमारी योजनाये, हमारे जो आर्थिक संकल्प है वे सब से पहले खतरे मे पड़ जाते हैं और हम इतने भयंकर तरीके से शीत युद्ध का शिकार हो जाएंगे जिससे कि हमारा उठना मुमकिन नही हो पाएगा। हम गुट-निरपेक्ष देशो के अगुआकार रहे है, हम यह तो नही कहते कि हमारा देश नेता रहा है, लेकिन दुनिया हमे जरूर नेता समझती है। इस सिलसिले म गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने अभी तक कोई ऐसा सकारात्मक रवैया नही अपनाया है कोई ऐसा पाजिटिव स्टैप नही लिया है जिससे उनकी भूमिका का भी पता चल सके। आज जो जनमत है उसको वार के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ तैयार करना चाहिए, उस सिलसिले मे भी हमारी सरकार और हमारी जनता काफी पीछे रही है। मेरा अनुरोध यह है कि पिछले दो तीन दिनो से इस सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है लेकिन सरकार अभी तक किसी भी वक्तव्य के साथ सदन मे नही आई है। मैं यह भी अपील करना चाहूगा कि उस सिलसिले मे, शांति स्थापित करने के सिलसिले मे, जग न होने के सिलसिले मे, युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए और यदि युद्ध हो जाता है तो ऐसी सूरत मे हमारा क्या कटेजेंसी प्लान होगा, इन तमाम चीजो को मद्देनजर रखते हुए इस सदन की और दोनो सदनो को विशेष रूप से समस्त संसद सदस्यो को कॉफिडेंस में, विश्वास में सरकार को लेना चाहिए और एक वक्तव्य के साथ, क्योंकि दो एक दिन के लिए सेशन बढ़ गया है, एक वक्तव्य के साथ सरकार को सदन के सामने आना चाहिए और भरसक प्रयास करने चाहिए कि यह जो जंग है, यह जो युद्ध है वह पूरी तरह से टाला जा सके। निश्चित रूप से यदि हमारी सरकार, हमारा देश आगे बढता है तो हो सकता है कि कोई सूरत निकल सके।

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Dr. J. K. JAIN, not here. Chaudhary Harmohan Singh.

Alleged misuse of urban land (Ceiling and Regulation) Act, 1976

चौधरी हरमोहन सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, शहरी भूमि सीमा रोपण अधिनियम के दुरुपयोग के संबंध मे आपने कुछ कहने का अवसर दिया उसके लिए मै आभारी हू। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अनुरोध है कि नगर भूमि सीमा अधिनियम अर्बन लैंड सीलिंग कानून 17 फरवरी, 1976 को पूरे देश में लागू हुआ जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों, जिला मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ, सहारनपुर के जिलों मे पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके उपरोक्त कानून के तहत प्रदेश के किसानो की 24 करोड़ वर्गमीटर भूमि एकतरफा एक्वायर कर ली गयी है। जबकि पूरे देश मे इस कानून का कोई प्रभाव नही रहा। दिल्ली जैसी जगहों मे 10-12 एकड़ सीलिंग मे पहचानी गयी जबकि कानपुर मे लगे हुए 252 गावो मे किसानो की 40 लाख वर्गमीटर भूमि लेकर सीलिंग विभाग द्वारा किसानो को नोटिस भेजकर कुर्की वारंट निकालकर किसानो को परेशान किया जा रहा है जिसके कारण किसान विचलित हो उठा है। नगर भूमि सीमा रोपण विभाग किसानों की उपजाऊ भूमि इस कानून के अंतर्गत लेकर 2 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे रहा है तथा किसानों की उसी